उत्तराखण्ड में (कोविड-१९) कोरोना का प्रभाव, रिवर्स पलायन के रूप में जनपद अल्मोड़ा का एक अध्ययन

डा0 मंजू चन्द्रा*

सारांश

प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध से कहीं अधिक भयानक है, नोबेल कोरोना वायरस की चुनौती। उन दोनों विश्व युद्धों में दुनिया के प्रमुख देश दो महाशक्तियों में बंटे हुए थे और उनका प्रभाव सीमित था। सीमित देशों के लोग शहीद भी हुए थे। मगर कोरोना वायरस का प्रभाव दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों में भी हो गया है। इससे लगभग सत्तर लाख से अधिक लोग प्रभावित हो चुके हैं और लगभग चार लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इससे जाहिर होता है कि कोविड–19 एक वैश्विक महामारी है। इससे दुनिया के अधिकांश देश जूझ रहे हैं। आज कोरोना आपदा वैश्विक आधार ले चुका है। दुनिया भर में मौतों की संख्या बढ़ती जा रही है और सभी शक्तिशाली देश इस वायरस के आगे लाचार दिखते हैं। अन्तिम विजय पाने के लिए जरूरी है कि संक्रमण की श्रृंखला टूटे और जिसके लिये सामाजिकता में कमी लानी ही होगी। लोकतंत्र के लिए यह बड़ी चुनौती होगी और इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि किसी का धैर्य न टूटे, जिससे वह सड़कों पर न आ जाये। कोरोना का सामाजिक संक्रमण के दौर में प्रवेश करना, हमारी स्वास्थ्य सेवाओं का चरमराना है और हमारी सफलता पूरे तरीके से फेल हो जायेगी।

मुख्य शब्द— 19, वैश्विक महामारी रिवर्स पलायन, प्रवासी जनपद अल्मोड़ा।

प्रस्तावना

कोरोना ने देश को कई खट्टे–मीठे अनुभव दिए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जनता कर्फ्यू है। जिसमें जवानों व किसानों की तरह स्वास्थ्यकर्मियों की भी जय–जयकार की गई। दुनिया भर में कोरोना की लड़ाई राष्ट्रीय समितियों और संस्थाओं से जुड़ी हुई है। हर देश अपने तरीके से इसका मुकाबला कर रहा है। अधिनायकतंत्र में जनता से सूचनाएं छिपाना आसान था, जिससे काफी दिनों तक वुहान में लोगों को पता ही नहीं चला कि आखिर हो क्या रहा है? तब तक शहर में हजारों लोग वुहान से भाग निकले और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय संक्रमण की शुरूआत कर दी। लाखों की आबादी वाले पूरे शहर को देश–दुनिया से अलग–थलग कर देना और घरों में बंद लोगों को खाने–पीने दवा तथा जरूरी सामान पहुंचाना, वाकई यह एक कहानी सी लगती है और इस महामारी के बीच यह सब इंसानों ने ही किया। विश्व मानकों पर ऊँचे पायदान पर स्थित इटली की स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ध्वस्त हो गयीं। जैसे–जैसे चीन का ग्राफ कम होता गया, इटली का ग्राफ बढ़ता गया। जिससे मृत्यु के आंकड़ों में इटली ने चीन को पछाड़ दिया। जिसमें कुछ प्रमुख देशों के आंकड़े आज दि0 10.6.2020 तक निम्नवत् देखे जा सके हैं।

क्र. सं.	प्रमुख देश	पुष्टि किए गए केस	ठीक हो चुके	मौतें
1	यूनाइटेड स्टेट्स	2002000	602000	114000
2	ब्राजील	742000	326000	38497
3	रसिया	494000	253000	6350
4	यूनाईट किंग्डम	290000	—	40883
5	भारत	278000	135000	7740
6	स्पेन	242000	150000	27130
7	इटली	236000	169000	34000
8	जर्मनी	187000	170000	8830

आंकड़े : जौन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एण्ड मेडीसन (कोरोना वा. रिसर्च सेन्टर)

* असिस्टेन्ट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, रा0महाविद्यालय, गुरूड़ाबांज

कोरोना वायरस अब तक दुनिया के कई देशों में फैल चुका है। अमेरिका, इटली, स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों में स्थिति बेकाबू हो गई है। इस महामारी से जहां पूरी दुनिया डरी हुई है, वहीं करोड़ों लोग घर के अन्दर कैद होने को मजबूर हैं, वहीं साल 2013 में रसायन शास्त्र का नोबल पुरस्कार जीतने वाले माइकल लेविट ने उम्मीद जताई है कि कोरोना का खतरा जल्द ही कम हो जायेगा। इसी के बीच कुछ देश व द्वीप ऐसे भी हैं, जो अभी तक इस वायरस से बचे हुए हैं और उनमें से ज्यादातर बेहद छोटे हैं। कोरोना का असर उन देशों पर ज्यादा पड़ा है, जहां पर दूसरे देशों के लोगों का आवागमन अधिक है। इसी वजह से दुनिया के ज्यादातर बड़े देश बुरी तरह इसकी चपेट में आ गए हैं। कोविड–19 की महामारी से लड़ाई में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे डाक्टर और नर्स हमारे युग के महानायक बन गए हैं, जिन्होंने दूसरों का जीवन बचाने के लिए खुद की जिन्दगी जोखिम में डाल दी है। इटली में कई डाक्टर व नर्सों की मौत हो चुकी है। कई अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मी बीमार हैं। कोरोना के कारण दुनिया भर में पड़ने वाले सामाजिक, आर्थिक असर से सम्बन्धित एक रिपोर्ट जारी करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने इस संकट को जिस तरह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बताया है यही मामले की गंभीरता जानने के लिए काफी है।

अध्ययन की आवश्यकता

महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम सभी उत्तराखण्ड वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि एक दिन हवाई जहाजों से कोरोना जैसी बीमारी भारत में और फिर उत्तराखण्ड में दस्तक देगी। साथ ही यह भी नहीं सोचा था कि कुछ सालों पहले तक शहरों की वजह से खाली होते उत्तराखण्ड के गांव अचानक भर जाएंगे। कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा किए गए 21 दिन के प्रथम लॉकडाउन के बाद से अपने गांव से पलायन करने वाले मजदूरों और गरीबों की एक लम्बी लाईन बार्डरों पर रोजाना देखने को मिली। इस बारे में जब लोगों से बात करनी चाही तो रिवर्स पलायन करने वालों का दर्द सामने आया। इनमें अधिकतर लोग दिल्ली, गुरूग्राम, गाजियाबाद, मुम्बई से थे, कुछ अन्य शहरों से भी थे, जो काफी परेशान थे जो चंद पैसों के लिए वर्षों पहले पलायन कर चुके थे और जिसमें से बचाकर वह हर महीने घर पैसा भेजा करते थे। लेकिन इधर न वेतन मिला, जितना मिला था उससे अभी तक काम चल रहा था। पर उनके पास कुछ बचा नहीं था, वह क्या खाते? कहां रहते? कम्पनियां/होटल सब बन्द हो गए। उनका कहना था एक बार अपने गांव पहुंच जाएं फिर दोबारा नहीं जाएंगे, वहां बीमारी से बच भी गए तो भूख से अवश्य मर जाएंगे। यह सभी लोग हजारों कि.मी. पैदल यात्रा कर अल्मोड़ा तक पहुंच चुके थे। इनमें कोरोना से अधिक भय भूख से मरने का दिख रहा था। कोरोना वायरस की महामारी ने उन्हें जिन्दगी के मायने और गांव का सुकून याद दिला दिया। यह सभी लोग कोरोना से लड़ाई के जरूरी हथियार "सोशल डिस्टेसिंग (Social Distancing)" को मानने और उसकी धज्जियां उड़ाने को मजबूर लोगों के बीच यह महसूस किया जा सकता है कि जब मौत सामने दिखती है तो जिन्दगी कितनी कीमती लगती है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हजारों बसों को चलाए जाने के ऐलान के बाद ये भीड़ आनन्द विहार में हजारों की संख्या में देखने को मिली। जो सभी लोग कोरोना व भूख से भागकर गांव की तरफ रिवर्स पलायन कर रहे थे। दिल्ली से अपने घरों के लिए दूसरे राज्यों को पलायन कर रहे मजदूरों को भोजन, परिवहन, मेडिकल सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 5 जनवरी को भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया और सरकार ने 17 जनवरी से इसकी तैयारियां शुरू कर दी थीं। साथ ही केन्द्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में बताया कि इस बात की सम्भावना है कि शहरों से ग्रामीण रिवर्स पलायन करने वाले 10 में से तीन व्यक्ति कोरोना वायरस ले कर जा सकते हैं। इसलिये लगभग 22.88 लाख प्रवासी मजदूरों, गरीबों और श्रमिकों को उनके गांव से अलग जगह पर रोका गया है, जबकि ये स्थिति सामुदायिक संक्रमण को न्यौता देने वाली है। अपने घरों को लौटने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और यह रिवर्स पलायन रूकने वाला नहीं है बल्कि बढ़ता रहेगा। स्थानीय जिला प्रशासन द्वारा मजदूरों को रोकने के लिए एक जगह इकट्ठा करना और खतरनाक साबित हो सकता है। इस दौरान कुछ माता–पिता ने अपने बच्चों को यह कह कर लौटा दिया कि पहले जांच करके आओ। जैसा कि बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा था कि बिहार लौट रहे लोगों को बसें उपलब्ध कराने से कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ेगा क्योंकि उनमें से कोई एक भी संक्रमित हुआ तो नतीजा घातक सिद्ध होगा और इससे महामारी उन छोटे गांवों में भी पहुंच सकती है जहां वो जा रहे हैं। अभी वर्तमान समय में उत्तराखण्ड में जो संक्रमित पाए गए हैं, वह इस सब का नतीजा है। जिसको वर्तमान समय में निम्न आंकड़ों द्वारा देखा जा सकता है :–

जिलावार विवरण : दिनांक 11.6.2020 तक

District	Total cases	Recoveries	Death	Active
Almora	74	62	01	11
Bageshwar	40	18	00	22
Chamoli	34	23	00	11
Champawat	48	27	01	20
Dehradun	403	139	09	225
Haridwar	154	45	00	109
Nainital	334	216	01	117
Pauri Garhwal	52	16	01	35
Pithoragarh	51	21	00	30
Rudraprayag	29	03	00	26
Total	**1563**	**749**	**13**	**800**

स्रोत : उत्तराखण्ड सरकार

आज उत्तराखण्ड के छोटे–छोटे गांवों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। जिन शहरों की नौकरियों की वजह से हजारों लोग अपने बच्चों को बड़ा और मां–बाप को बूढ़ा होते नहीं देख पाए होंगे वो आज इस स्थिति में गांव लौटे हैं। गांव के लगभग हर परिवार का सदस्य शहर में छोटा–मोटा काम करता है और वक्त बेवक्त वहां से थोड़ा बहुत पैसा घर भेज दिया करता है। अब कोरोना वायरस की इस भगदड़ में वो कितने दिन गांव में बिताएंगे और कैसे? कुछ लोग गांव में खेतीबाड़ी या गांव में ही कोई रोजगार के भरोसे लौटे हैं। अगर इन नौजवानों ने हौसला बनाए रखा या इस महामारी के सबक से वह गांव में रहकर सरकार द्वारा चलाई गई विभिन्न योजनाओं का लाभ लेकर छोटा–मोटा रोजगार करना प्रारम्भ करें, साथ ही खेती–बाड़ी शुरू कर दें तो निश्चित ही यह काफी हद तक बरसों पहले हुए गांवों से पलायन को रिवर्स कर सकता है। शायद इसी बहाने वह लोग अपने टूटे–फूटे घरों की मरम्मत करवाएं, खेत व फसल से जुड़ाव महसूस करें और गांव में रहकर यह जान पाएं कि जरूरतों की थाली कभी नहीं भरती, थाली में एक महत्वपूर्ण कटोरा प्यार व सुकून का होना भी अति आवश्यक है।

अध्ययन के उद्देश्य

वर्तमान में पलायन उत्तराखण्ड की विकराल समस्या बन चुका है, मगर उत्तराखण्ड में गांवों से लोगों के पलायन होने के जितने कारण हैं उससे कई अधिक सम्भावनाएं पलायन को रोकने की भी हैं। जब से उत्तराखण्ड राज्य अस्तित्व में आया है, तब से पलायन निरन्तर बढ़ता ही जा रहा है। पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के हजारों गांव पूरी तरह खाली हो चुके हैं, वहीं 400 से अधिक गांव ऐसे हैं जहां दस से भी कम नागरिक हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सन् 1991 से 2001 के बीच दस सालों में सात करोड़ तीन लाख ग्रामीणों ने पलायन किया। इनमें से पांच करोड़ तीस लाख लोग एक गांव छोड़कर दूसरे गांव में बसने चले गए। लगभग दो करोड़ लोगों ने शहरों को पलायन किया। इनमें से अधिकतर लोग काम की तलाश में गए।

जनगणना 2011 के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या 121.02 करोड़ आकलित की गयी है, जिसमें 68.84 प्रतिशत जनसंख्या गांव में निवास करती है और 31.16 प्रतिशत जनसंख्या शहरों में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना 1951 में ग्रामीण एवं शहरी आबादी का अनुपात 83 प्रतिशत ग्रामीण एवं 17 प्रतिशत शहरी था। 50 वर्ष बाद 2001 की जनगणना में ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या 74 एवं 26 हो गया। इन पिछले आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि भारतीय ग्रामीण लोगों का शहरों की ओर पलायन तेजी से बढ़ा है। इसी क्रम में अगर हम पलायन एवं वर्तमान रिवर्स पलायन के आधार पर जनपद अल्मोड़ा की स्थिति पर एक नजर डालें तो पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनपद अल्मोड़ा में 70 हजार लोगों ने पलायन किया है। राज्य की 646 पंचायतों के 16207 लोग स्थाई रूप से अपना गांव छोड़ चुके हैं। आयोग ने मूलभूत सुविधाओं की कमी को पलायन की मुख्य वजह बताया है।

अल्मोड़ा, उत्तराखण्ड के पूर्व में स्थित कुमाऊँ मण्डल का एक पहाड़ी जिला है। समुद्रतल से लगभग 1638 मीटर की ऊँचाई पर स्थित इस जनपद के पूर्व में पिथौरागढ़, पश्चिम में गढ़वाल मण्डल, उत्तर में बागेश्वर और दक्षिण में नैनीताल जनपद स्थित है। जनपद का कुल क्षेत्रफल 3139 वर्ग कि.मी. है। जिसमें लगभग 1309 वर्ग कि.मी. वन क्षेत्रफल है। जनपद अल्मोड़ा अपने समृद्ध इतिहास, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत, सुन्दर परिदृश्य, हस्त शिल्प और भोजन के लिए प्रमुखतया जाना जाता है। अल्मोड़ा शहर की स्थापना चंद राजवंश के 43वें शासक, राजा भीष्म चंद ने 1530 ई0 में की थी। सन् 1864 में ब्रिटिश शासन के तहत छावनी, चर्च और सर्किट हाउस आदि कई आर्किट्रेक्चर बनाए गए थे। अल्मोड़ा नगर पालिका उत्तराखण्ड की सबसे पुरानी नगर पालिका है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल जनसंख्या 622506 थी, जिसका जनसंख्या घनत्व प्रति व्यक्ति 198 वर्ग कि.मी. है। जनपद की 89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। वर्ष 2016–17 के लिए औसत जन्म दर और मृत्यु दर क्रमशः 15.80 प्रतिशत और 6 प्रतिशत है। जनपद में 140577 परिवार हैं जो कि राज्य में कुल परिवारों का 6.83 प्रतिशत है। 2001–2011 के दौरान जनपद की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर अर्थात 1.64 प्रतिशत दर्ज की गई है। पिछली कई जनगणनाओं में जनपद की आबादी में लगातार गिरावट देखी गयी है। वर्ष 2001 में जनसंख्या वृद्धि दर 3.67 प्रतिशत हुई तथा 2011 की जनगणना में यह दर 1.64 प्रतिशत रह गयी थी।

जनपद को प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से 6 उपखण्डों में विभाजित किया गया है। 12 तहसीलें, 2 उप तहसीलें और 11 विकास खण्ड हैं, इसके अतिरिक्त जनपद में 95 न्याय पंचायतें, 1166 ग्राम पंचायतें और 2289 ग्राम हैं, जिसको निम्न तालिका से समझाया गया है :–

जनपद	उपखण्ड	तहसीलें	विकास खण्ड
अल्मोड़ा	1. अल्मोड़ा	1. सोमेश्वर	1. स्याल्दे
	2. जैंती	2. जैंती	2. चौखुटिया
	3. द्वाराहाट	3. भनोली	3. भिकियासैंण
	4. रानीखेत	4. लमगड़ा (उप तहसील)	4. ताड़ीखेत
	5. भिकियासैंण	5. द्वाराहाट	5. सल्ट
	6. सल्ट	6. जालली	6. ताकुला
		7. बगवालीपोखर	7. भैंसियाछाना
		8. रानीखेत	8. हवालबाग
		9. भिकियासैंण	9. लमगड़ा
		10. स्याल्दे	10. धौलादेवी
		11. सल्ट	11. द्वाराहाट
		12. मछोड़ (उप तहसील)	

जनपद में जनसंख्या वितरण

वर्ष/विकास खण्ड	क्षेत्रफल वर्ग कि. मी.	कुल जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या	शहरी जनसंख्या	ग्रामीण जनसंख्या में % परिवर्तन	शहरी जनसंख्या में % परिवर्तन
1991	3697	610453	562718	47735	8.41%	–
2001	3139	632866	578361	54505	2.78%	14.18%
2011	3139	622506	554096	68410	–4.20%	25.51%
विकासखण्ड वार (2011)						
स्याल्दे	241.4	44747	44747	–	–9.17%	–
चौखुटिया	192.1	46039	4639	–	–6.08%	–
भिकियासैंण	214.06	28962	28962	–	–21.78%	–
ताड़ीखेत	241.32	64063	64063	–	–7.45%	–
सल्ट	302	56095	5695	–	–8.85%	–
द्वाराहाट	207.4	60066	60066	–	–2.42%	–
ताकुला	113.6	45883	55883	–	1.23%	–
भैंसियाछाना	96.4	26634	26634	–	0.85%	–
हवालबाग	198.76	67447	67447	–	0.28%	–
लमगड़ा	214.2	52169	52169	–	10.18%	–
धौलादेवी	324.4	60620	60620	–	–3.54%	–
योग विकास खण्ड	**2345.64**	**552725**	**552725**	**68697**	**–4.20%**	–
वन	751.2	814	814	–	–4.25%	–
ग्रामीण क्षेत्रफल	3096.84	553539	553539	68967	–4.20%	–
शहरी क्षेत्रफल	42.16	68967	0	–	–	25.51%
योग जनपद	**3139**	**622506**	**553539**	**68967**	**–4.20%**	

आज जनपद के युवा अपनी आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि बेहतर अवसरों के लिए राज्य, देश या विदेश के शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं। जनपद की साक्षरता दर 80.47% है, जिसमें पुरूष व महिला साक्षरता दर क्रमशः 92.86% और 69.93% है। अल्मोड़ा एक पर्वतीय जनपद है, अर्थव्यवस्था का अधिकांश भाग परम्परागत कृषि, बागवानी, पशुधन, वन एवं लौगिंग, खनन पर निर्भर करता है। हालांकि कृषि आजीविका का प्रमुख स्रोत है परन्तु वर्तमान समय में कृषि व प्राथमिक योगदान दोनों घट रहा है क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या का केवल 1.51% ही इस क्षेत्र में लगी हुई है। कृषि की उत्पादकता में कमी तथा आजीविका के विकल्पों की अनुपलब्धता के कारण कामकाजी आयु वर्ग के युवा बेहतर अवसरों की तलाश में नजदीकी शहरों या राज्यों की ओर पलायन कर चुके हैं। जबकि जनपद में स्लेट, चूना, पत्थर, मैग्नेसाइट, सल्फर, लिग्नाइट, ग्रेफाइट इत्यादि खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं। भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र होने के कारण एवं जैव विविधता को नुकसान होने के कारण संसाधनों का दोहन नहीं किया गया है।

पिछले 10 वर्षों में 1022 ग्रामों/तोकों से कुल 53611 व्यक्तियों द्वारा अस्थायी रूप से पलायन किया गया है, हालांकि वह समय–समय पर अपने घरों में आते–जाते रहते हैं क्योंकि उनके द्वारा स्थायी रूप से पलायन नहीं किया गया है। वहीं पिछले 10 वर्षों में 646 ग्राम/तोकों से 16207 व्यक्तियों द्वारा पूर्ण रूप से स्थायी पलायन किया जा चुका है। आंकड़ों से जानकारी मिलती है कि स्थायी पलायन की तुलना में अस्थायी पलायन अधिक हुआ है।

पिछले 10 वर्षों में जनपद अल्मोड़ा में विकास खण्ड वार पलायन

जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत ग्राम/तोक जहां अस्थायी पलायन हुआ है	पिछले 10 वर्षों में अल्पकालीन पलायन करने वाले लोग	ग्राम पंचायत/ग्राम/तोक स्थायी पलायन करने वाले गांव में भूमि बेचकर गए। आने की संभावनाएं नहीं हैं	पिछले 10 वर्षों में स्थायी पलायन भूमि बेच कर गए। गांव में आने की संभावना नहीं
अल्मोड़ा	भैंसियाछाना	51	3493	37	1215
अल्मोड़ा	भिकियासैंण	91	5752	74	1344
अल्मोड़ा	चौखुटिया	91	5657	35	1148
अल्मोड़ा	धौलादेवी	93	4948	39	1013
अल्मोड़ा	द्वाराहाट	121	9038	92	3507
अल्मोड़ा	हवालबाग	78	2023	50	555
अल्मोड़ा	लमगड़ा	99	4229	77	1599
अल्मोड़ा	सल्ट	123	3480	77	1379
अल्मोड़ा	स्याल्दे	88	4723	47	1098
अल्मोड़ा	ताकुला	82	6498	61	2056
अल्मोड़ा	ताड़ीखेत	105	3770	57	1293
	कुल	**1022**	**53611**	**646**	**16207**

उपरोक्त पलायन के मुख्य कारण आजीविका/रोजगार की कमी, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शिक्षा सुविधाओं में कमी, सड़क, बिजली, पानी आदि बुनियादी सुविधाओं में कमी एवं कृषि उत्पादन में कमी हैं। जिसका कारण मुख्य रूप से जंगली जानवरों के आतंक से परेशान होकर किया गया पलायन और कुछ देखा–देखी भी पलायन किया गया है। ग्राम पंचायतों से पलायन करने वाले आंकड़ों के अनुसार ज्ञात हआ है कि लगभग 42 प्रतिशत पलायन 26 से 35 वर्ष के आयु वर्ग द्वारा किया गया है और लगभग 35 प्रतिशत पलायन राज्य के अन्य जनपदों में हुआ है जबकि 28 प्रतिशत पलायन राज्य के बाहर हुआ है।

कोरोना महामारी के बाद बीते दिनों में करीब 9 हजार लोग शहरों को छोड़कर अपने गांव लौट आए हैं। फिलहाल इनमें से कई लोग स्थितियों के सामान्य होने का इन्तजार कर रहे हैं। साथ ही यह माना जा रहा है कि वापस लौटे कई लोग अपने गांव में ही कुछ स्वरोजगार का मन बना सकते हैं। प्रशासन एवं ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में पलायन से अधिक प्रभावित गांवों में लोगों से बात कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ देकर प्रोत्साहित किया जायेगा और उन्हें खेतीबाड़ी, दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन, सौर ऊर्जा, खादी ग्रामोद्योग आदि योजनाओं का लाभ देकर मदद की जायेगी। लॉकडाउन के कारण जनपद में अपने घरों को वापस लौटे प्रवासी स्वरोजगार अपना कर अपनी आजीविका चला सकते हैं और सरकार भी चाहती है कि घर वापसी करने वाले प्रवासी यदि 30 फीसदी भी रूके तो सरकारी योजनाओं की मदद से वे रिवर्स पलायन के लिए उत्प्रेरक का काम कर पाएंगे। सरकार उनकी वापसी को रिवर्स पलायन में बदलने की भरसक कोशिशों में जुटी है। 18 मई 2020 तक जनपद अल्मोड़ा में 34530 प्रवासी अपने गांव लौटे हैं। हालांकि उत्तराखण्ड राज्य के लिए यह अच्छा संकेत है, बशर्ते वे गांव में ही बने रहें। लेकिन लॉकडाउन की पाबंदियों में ढील मिलने के साथ प्रवासियों की वापसी लगभग बंद हो गयी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह महानगरों में उद्योगों व अन्य कारोबार खुलना है जो कि बेरोजगार हो चुके लोगों के लिए एक अच्छा संकेत भी है। महानगरों से प्रवासियेां के पहुंचने के बाद गांवों के लोग दहशत

में हैं। कई गांवों में लोगों ने घरों से बाहर निकलना बंद कर दिया। क्योंकि होम क्वारेन्टाइन किए गए लोगों द्वारा नियमों का सही पालन नहीं किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा इनकी निगरानी का कार्य ग्राम प्रधानों को दिया गया है, लेकिन यह भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। जबकि लॉकडाउान के चलते उत्तराखण्ड में लौटे लोगों के कारण पहाड़ी जिलों की जीडीपी में गिरावट आने की आशंका है। लॉकडाउन में देहरादून, हरिद्वार और यू.एस.नगर को छोड़कर राज्य के शेष 10 जिलों में 59360 प्रवासी अपने गांव लौट आये हैं। अचानक हुए रिवर्स पलायन को पहाड़ में ही थामने और इस प्रशिक्षित मानव संसाधन के बेहतर प्रयोग के लिए पलायन आयोग ने मुख्यमंत्री को प्रारम्भिक रिपोर्ट भेज दी है। आयोग की रिपोर्ट के अनुसार घर लौटे प्रवासी अधिकतर 30–40 आयु वर्ग के हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। जो श्रम कर राज्य की बेहतरी के लिए भी कार्य कर सकते हैं। पलायन आयोग उपाध्यक्ष एस.एस. नेगी की रिपोर्ट के अनुसार पहाड़ी जिलों में 35 फीसदी रिवर्स पलायन तो राज्य के भीतर से ही हुआ है। जबकि करीब साठ फीसदी देश के दूसरे प्रदेशों से हुआ है। करीब पांच प्रतिशत लोग विदेशों से आए हैं। इस मानव संसाधन के बेहतर इस्तेमाल के लिए आयोग ने सरकार को प्रारम्भिक सुझाव भेज दिए हैं। जनपद की 11 विकास खण्डों में से 7.13 प्रतिशत लोगों ने गावों के नजदीकी शहरी क्षेत्रों में पलायन किया है, जबकि 13 प्रतिशत लोगों ने जनपद मुख्यालय, 32.37 प्रतिशत ने प्रदेश के अन्य जनपदों में, 47.08 प्रतिशत लोग राज्य से बाहर पलायन कर चुके हैं। देश के बाहर पलायन करने वालों की संख्या 0.43 प्रतिशत है। 2011 के बाद जनपद के 80 गांवों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव में 50 प्रतिशत से अधिक आबादी कम हुई है। वहीं 63 गांवों में सड़क, 11 गावों में बिजली, 34 गांवों में एक किलोमीटर के दायरे में पेयजल न होने और 71 गांवो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की सुविधा न होने से 50 प्रतिशत आबादी घटी है। जिसको निम्नवत् समझा जा सकता है।

- ➢ वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा जनपद की जनसंख्या 6 लाख 22 हजार 506 है।
- ➢ 89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
- ➢ जनपद अल्मोड़ा का क्षेत्रफल 3189 वर्ग किलोमीटर है।
- ➢ अल्मोड़ा जनपद में निवास करने वाले परिवारों की संख्या 1 लाख 40 हजार 577 है।
- ➢ अल्मोड़ा जनपद के शहरी क्षेत्रों की आबादी में 25 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई है।

विकास खण्ड वार गांवों से हुए पलायन की स्थिति :

विकास खण्ड अन्य जनपद	**नजदीकी नगर राज्य से बाहर**	**जनपद मुख्यालय देश से बाहर**
भैंसियाछाना 38.96	1.80 45.85	13.37 0.01
भिकियासैंण 23.67	5.38 60.65	9.98 0.33
चौखुटिया 30.90	8.71 53.03	7.16 0.20
धौलादेवी 44.23	4.02 36.09	156.6 —
द्वाराहाट 31.37	13.52 42.52	11.29 1.29
हवालबाग 35.00	6.25 46.25	12.50 —
लमगड़ा 40.23	13.94 19.52	25.91 0.40
सल्ट 27.46	10.38 50.15	11.69 0.31
स्याल्दे 29.04	1.53 59.61	9.76 0.07
ताकुला 29.80	2.31 52.67	15.04 0.18
ताड़ीखेत 32.65	8.60 47.76	9.97 1.01

जनपद अल्मोड़ा में भी मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोगों ने पलायन किया है। इन सभी ब्लाकों में कई गांवों में सड़क, पेयजल, बिजली और आजीविका के साधन नहीं हैं, जिससे लोग जनपद मुख्यालय और प्रदेश के अन्य नजदीकी शहरों में बस गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना ही उत्तराखण्ड के पलायन का सबसे बड़ा मर्ज है। अल्मोड़ा को लेकर किए गए पलायन विभाग के अध्ययन में यह बात सामने आयी है कि जलवायु परिवर्तन आने वाले समय में पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि और बागवानी को प्रभावित करेगा। इसलिये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कृषि बागवानी के अलावा अन्य आर्थिक संसाधन तलाशने होंगे। साथ ही पर्यटन यहां अहम भूमिका निभा सकता है। 90 फीसदी ग्रामीण क्षेत्र वाले अल्मोड़ा में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर 4.20 प्रतिशत है जबकि जनपद की जनसंख्या दर 1.64 प्रतिशत है। अल्मोड़ा की आबादी में इस गिरावट की वजह पलायन है। 20 से 45 वर्ष आयु के बीच के कामकाजी लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की वजह से राज्य, देश, विदेश में पलायन कर रहे हैं। आज पलायन की समस्या से निपटने के लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

एक तरफ जहां शहरी चकाचौंध, भागमभाग की जिन्दगी, उद्योगों, कार्यालयों तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों में रोजगार के अवसर परिलक्षित होते हैं, वहीं गांव में पाये जाने वाली रोजगार की अनिश्चितता, प्राकृतिक आपदा, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, शिक्षा के अभाव ने लोगों को पलायन के लिए प्रेरित किया है। शहरो में अच्छे परिवहन के साधन, शिक्षा केन्द्र, स्वास्थ्य सुविधाओं एवं अन्य सेवाओं ने भी गांवों के युवाओं, महिलाओं को आकर्षित किया है। इससे कई प्रकार के असंतुलन भी पैदा हो रहे हैं। वहीं गांवों में कामगारों की कमी का अनुभव किया जा रहा है।

निष्कर्ष

गांवों में पलायन को रोकने के लिए उन्हें आधुनिक तरीके से कृषि करने के तौर तरीकों का प्रशिक्षण देना जरूरी है। फलदार, लेमनग्रास, नींबू, सेब आदि पौधे लगवाकर रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों के दुर्गम गांवों को संवारने की अधिक आवश्यकता है। पहाड़ों से पलायन कर चुके लोग रिवर्स पलायन करेंगे तभी गांवों का विकास स्तर बढ़ेगा। इसके साथ ही रोजगार के आयाम स्थापित होंगे। गांवों को अधिकाधिक सुविधायुक्त बनाने की आवश्यकता है। जैसे गांवों को पक्के सड़क मार्ग से जोड़ना, बिजली व पानी जैसी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति, हर गांव में कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सालय, आवश्यक सेवा प्रदान करने हेतु एक डाक्टर, दवाओं की उचित व्यवस्था, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल, युवाओं के लिए उद्योग धन्धे आदि। इन सब को अगर सकारात्मक दृष्टि से देखा जाय तो गांवों में कारोबार, रोजगार व कमाई के साधन ही खड़े नहीं होंगे अपितु आने वाले समय में अर्थव्यवस्था को एक नई ताकत भी मिल सकती है क्योंकि पलायन की प्रवृत्ति कई रूपों में देखने को मिलती है जैसे एक गांव से दूसरे गांव में, गांव से नगर में, नगर से नगर में, नगर से गांव आदि। परन्तु उत्तराखण्ड के गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति कुछ ज्यादा है। अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर रहना और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करना पलायन की प्रवृत्ति है।

निश्चित ही गांवों का विकास होने से यह सब रूकेगा, साथ ही शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और शिक्षा व स्वास्थ्य के माध्यम से आदर्श गांव स्थापित होंगे। जिससे पलायन रूकेगा। जनपद अल्मोड़ा में भी कई ऐसी जगह हैं जिससे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। वर्तमान में अल्मोड़ा के किसान पारम्परिक खेती से दूर हो रहे हैं, इसलिये सिर्फ कृषि व बागवानी पर ध्यान देने की जगह अन्य माध्यमों से ग्रामीण आय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जनपद अल्मोड़ा में कई ऐसे गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची हैं, पीने के पानी की समस्या है, सिंचाई के पानी की समस्या है, अच्छे स्कूल नहीं हैं। ऐसे गांवों में ही सबसे अधिक पलायन हुआ है। अल्मोड़ा जनपद में चाय बागानों को भी बढ़ाया जा सकता है। जिसके लिए स्थानीय किसानों को ही लीज पर जमीन देना उचित होगा। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बड़े साधन के रूप में उभरा है। वर्ष 2016–17 में 11.77 लाख लोगों के मुकाबले वर्ष 2017–18 में 14.14 लाख लोगों ने मनरेगा के तहत श्रम किया है। इसमें 55 प्रतिशत महिलाओं की हिस्सेदारी है। अल्मोड़ा जनपद में सल्ट, स्याल्दे, भिकियासैंण और भैंसियाछाना विकास खण्ड सबसे पिछड़े पाए गए हैं। इसके साथ ही स्वयं सहायता समूहों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और ग्रामीण पर्यटन को मजबूत करने के लिए इको टूरिज्म, होम स्टे योजना एवं स्थानीय त्यौहारों में पर्यटकों को रिझाने का प्रयास किया जा सकता है।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रदेश के हर गांव तक सड़क पहुंचाने, 18 वर्ष से अधिक आयु के अनाथ, युवाओं को सहारा देने हेतु वात्सल्य योजना बनाने, रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए प्रवासी उत्तराखण्डियों की समस्या के निराकरण हेतु अलग विभाग बनाने आदि घोषणाएं की हैं। अगर सचमुच यह कार्य धरातल पर हुआ तो अवश्य ही कोरोना वायरस के साथ हुआ रिवर्स पलायन निश्चित ही कारगर सिद्ध हो सकता है। सीमांत गांवों को धीरे–धीरे फलने–फूलने से कोई नहीं रोक सकता।

पलायन आयोग के उपाध्यक्ष एस.एस.नेगी के मुताबिक नवम्बर में राज्य स्थापना दिवस पर टिहरी में आयोजित सम्मेलन में सरकार ने प्रवासी उत्तराखण्डियों के बीच पलायन की समस्या पर मंथन किया। अब इसी कड़ी में सरकार ऐसे लोगों से भी बात करेगी जिन्होंने पहाड़ में फिर से रोजी–रोटी कमाने के लक्ष्य से वास्तविक रिवर्स पलायन किया है। उन्हें गांव में आजीविका के साधनों से तैयार करेगी। साथ ही एक रूप रेखा तैयार कर देहरादून में एक सम्मेलन कर रिवर्स पलायन युवाओं से उनके तजुर्बे लिए जाएंगे।

आयोग की रिपोर्ट में रिवर्स माइग्रेशन के लिए भी कवायद किए जाने का उल्लेख है। रिपोर्ट की लौन्चिंग करते समय सी.एम. त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि अल्मोड़ा में पलायन की दर काफी ज्यादा है, ऐसे में रिवर्स माइग्रेशन के लिए कवायद की जायेगी ताकि लोग गांवों की ओर लौटें। इसके लिए स्वयं सहायता समूहों के जरिये कृषि, बागवानी और लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जायेगा एवं टूरिज्म के लिए होम स्टे स्कीम को भी बढ़ावा दिया जायेगा। एस.एस. नेगी द्वारा यह भी बताया गया कि सामाजिक, आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने व पलायन को कम करने के लिए राज्य के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर विशेषज्ञों व स्थानीय लोगों के साथ विचार–विमर्श किया गया। विभिन्न विश्वविद्यालयों व संस्थाओं के विशेषज्ञों, पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन पर अंकुश लगाने के लिए विषय विशेषज्ञों व छात्रों से भी सुझाव लिए गए। शासन स्तर पर भी बैठकें आयोजित की गयीं। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्मोड़ा के बाद पिथौरागढ़ और टिहरी के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन की वजहों को जानने और उसे दूर करने के उपायों को लेकर रिपोर्ट तैयार की जायेगी।

उत्तराखण्ड से राज्य सभा सांसद अनिल बलूनी ने उत्तरखण्ड में हो रही भारी पलायन की समस्या के निदान हेतु पर्वतीय जनपदों के लिए आगामी बजट में 'विशेष फण्ड' की मांग देश के वित्त मंत्री को प्रस्तुत की है। अगर सांसद बलूनी की यह मांग स्वीकार्य होती है तो उत्तराखण्ड के पर्वतीय जिलों के लिए 'विशेष फण्ड' व्यवस्था मील का पत्थर साबित होगी और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस हिमालयी राज्य के लिए जीवनदान होगा।

हमारे देश की ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत निरन्तर घट रहा है, जिसके पीछे मुख्य कारण गांवों से शहरों की ओर पलायन है और यह कोई नया मामला नहीं है। आज देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए गांवों में बुनियादी विकास की मूल आवश्यकता है। गांवों में शहरों जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी। देश में व्याप्त कुरीतियों को नष्ट करना होगा तथा शिक्षा की अलख जगानी होगी। शिक्षा के माध्यम से ही ग्रामीण जनता में जन चेतना का उदय होगा तभी वे विकास की मुख्य धारा से जुड़ सकेंगे। अर्थात कोरोना वायरस के प्रभाव से हुए इस रिवर्स पलायन का पूर्ण सदुपयोग कर इस देव भूमि को जीवित कर विकसित किया जा सकता है। जनपद अल्मोड़ा हमारी सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। साथ ही पर्यटन का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अगर ईमानदारी से एक ठोस पर्यटन नीति बनाई जाए तो काफी हद तक माईग्रेशन रूक सकता है। बस जरूरत है एक दृढ़ इच्छाशक्ति की, एक ईमानदार सरकार की जो इसको गंभीरता से ले, साथ ही लोगों के सहयोग की, एक ऐसे जन प्रतिनिधि की जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए अपने क्षेत्र में न जाए, बल्कि क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का समाधान करे, उनके दुःख–दर्द को समझे। अगर ऐसा हो जाए तो वह दिन दूर नहीं होगा जब उत्तराखण्ड के लोग वापस अपने पहाड़ों में, गांवों में लौटने लगेंगे। वर्तमान में जो वायरस के कहर से लौटे हैं वह यहीं बस सकेंगे। हम उत्तराखण्ड के गांवों को फिर से हरा भरा देख सकेंगे और रिवर्स पलायन को साकार कर सकेंगे।

जीने का सबब ढूंढने आया था,
सबक लिए जा रहा हूँ।
कुछ जख्मों को साथ लेकर जा रहा हूँ,
आज मैं अपने घर जा रहा हूँ।
सपने लेकर आया था,
कड़वी यादें ले जा रहा हूँ,
कंधों पर जिम्मेदारियां, भर जा रहा हूँ,
आज मैं अपने घर जा रहा हूँ।
शायद अब लौटकर न आऊंगा,
कुछ पोटली में गफलत लिए जा रहा हूँ
इन शहरों से नफरत लिए जा रहा हूँ
आज मैं अपने घर जा रहा हूँ।

(श्रेयांश डागर–एक प्रवासी मजदूर)

संदर्भ ग्रंथ सूची

(क) प्राथमिक स्रोत – अध्ययन क्षेत्र सर्वेक्षण

(ख) द्वितीयक स्रोत

1. जोशी आलोक, हिन्दुस्तान, सोमवार 6 अप्रैल, 2020, पेज 8
2. अमर उजाला, 6 अप्रैल, 2020, पृ0सं0 08
3. अमर उजाला, 24 मार्च, मंगलवार, पृ0सं0 8
4. सिंह हरिकेश, हिन्दुस्तान टाइम्स, 5 अप्रैल 2020,रविवार, पृ0सं0 11
5. अमर उजाला, 2 अप्रैल, 2020, पृ0सं0 6
6. नेगी, डा0एस0एस0, उपाध्यक्ष, पलायन रिपोर्ट
7. अमर उजाला, रविवार, 18 सितम्बर, 2016, पृ0सं006
8. अमर उजाला, बृहस्पतिवार, 9 अप्रैल, 2020, पृ0सं0 06, 08
9. https://almora.nic.in
10. जनगणना 2011 आलेख
11. सांख्यिकी पत्रिका, अल्मोड़ा
12. Uttarakhand Migration Commission Report – 2018
13. अमर उजाला, 26 अप्रैल, 2020 रविवार, पृ0सं0 08
14. हिन्दुस्तान टाइम्स, 1 जून, 2020, सोमवार पृ0सं0 08
15. अमर उजाला, 18 मई, 2020, सोमवार पृ0सं0 03
16. हिन्दुस्तान टाइम्स, 22 अप्रैल, 2020 बुधवार, पृ0सं0 – 02
17. www.covindindia.org/uttarakhand
18. जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एण्ड मेडीसन (कोरोना वायरस रिसर्च सेन्टर) आंकड़े
19. www.amarujala.com
20. uttarakhandpost.com